RNI : UAHIN/25/A3210

आवाम इंडिया

हिन्दी साप्ताहिक

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए 24 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। पेज 3

वर्षः 01 अंकः 13 देहरादून, शुक्रवार 10 जुलाई 2026 मूल्य 2 रुपये पृष्ठः 8 www.aawamindia.com

उत्तराखण्ड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त

देहरादून। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने उत्तराखंड में बारिश की संभावना जताई हुई है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से हरिद्वार का आम जनजीवन प्रभावित हो गया। बारिश ने हरिद्वार में जलनिकासी व्यवस्था की भी पोल खोल दी। सुबह शहर के कई प्रमुख चौराहे जलमग्न हो गए, जिससे यातायात प्रभावित रहा और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर दो से तीन फीट तक पानी भर गया। वहीं चंद्राचार्य चौक और सिटी अस्पताल के बाहर भी जलभराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई दुकानों में भी बारिश का पानी घुसने से व्यापारियों को नुकसान हो गया। साथ ही दुकानों के बाहर खड़े वाहन भी आधे पानी में डूबते नजर आए। भगत सिंह चौक के पास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक निजी बस फंस गई.चंद्राचार्य चौक के पास एक कार पानी में बंद हो गई। लिहाजा कार सवारों ने धक्का लगाकर कार को पानी से बाहर निकाला। इसके अलावा दोपहिया वाहन बीच पानी में ही बंद हो गए। जलभराव के कारण फैक्ट्री और कॉलेज जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस क्षेत्र में निगम प्रशासन ने बरसात से पहले ही साफ सफाई कराई थी लेकिन यहां जलभराव की समस्या करीब तीस साल पुरानी है। जिसका आज तक स्थाई समाधान नहीं हो पाया. यहां से भेल क्षेत्र के बड़े नाले में पानी आता है और सीधा गंगा में पानी की निकासी होती है। जल निकासी

के लिए चंद्राचार्य चौक पर पंप लगाए गए हैं लेकिन तेज बारिश में पंप भी काम नहीं कर सके। जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हरिद्वार में बारिश के चलते कनखल के लाटोवाली क्षेत्र में भी यही स्थिति देखने को मिली। यहां सड़कों पर करीब तीन फीट तक पानी भर गया। यहां पानी भरने से लोगों की आवाजाही बंद हो गई। घरों के बाहर खड़े वाहन भी आधे डूबे नजर आए। यहां भी जलभराव की समस्या वर्षों पुरानी है, जिसका स्थाई समाधान आज तक नहीं हो पाया. इसके साथ ही ज्वालापुर क्षेत्र में भी बाजार में पानी भर गया। पुरानी बनी दुकानों में अंदर तक पानी घुस गया. जिसके चलते दुकानदारों को नुकसान की आशंका है. ज्वालापुर शहर का मुख्य बाजार है। आबादी बढ़ने के साथ यहां जलनिकासी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया और ड्रेनेज प्लान की मांग आज भी अधूरी है. हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर गैंडीखाता क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने बनी पुलिया का एक हिस्सा अचानक धंस गया। एनएचएआई के द्वारा अभी हाल ही में इस पुलिया निर्माण कराया गया था। घटना के समय मार्ग से गुजर रही उत्तराखंड रोडवेज की एक बस पुलिया के धंसने से उसमें फंस गई, बस में सवार दर्जनों यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया।

चालक की सूझबूझ से बस को पुलिया से बाहर निकाला गया। लेकिन बस के टायर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा. सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बस को साइड में लगाकर यातायात सुचारू कराया। फिलहाल सड़क के आधे हिस्से से आवाजाही कराई जा रही है. बारिश बंद होने के बाद पुलिया की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पांच जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाकी जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इन जिलों में येलो अलर्ट है। इधर बारिश और लैंडस्लाइड ने उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है। मसूरी में 100 साल पुराना पेड़ गिर गया। उत्तरकाशी में सड़कों के खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होगी। राज्य के बाकी बचे 8 जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होगी. इस दौरान बादल जोर से गरजेंगे और बिजली भी चमकेगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार 10 जुलाई के लिए पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार इन सभी दिनों में राज्य में बारिश होगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका भी जताई है। राजमार्गों में अवरोध और कटाव हो सकता है। इस दौरान बिजली गिरने का आशंका भी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। अपर माल रोड स्थित बेकरी हिल के पास अचानक 100 साल पुराना एक विशालकाय पेड़ भरभराकर सड़क पर गिर पड़ा। पेड़ की चपेट में एक कार और सड़क किनारे खड़ी तीन स्कूटी आ गईं।

राहत की बात यह रही कि घटना के समय किसी वाहन में कोई सवार नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। जो पेड़ गिरा वो खाखसी प्रजाति का बताया गया है। पेड़ गिरते ही अपर माल रोड पर अफरा-तफरी मच गई. सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पर्यटक और स्थानीय लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहे। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और संयुक्त अभियान शुरू किया। भारी-भरकम पेड़ को हटाना आसान नहीं था. फायर सर्विस के जवानों ने कटर मशीन की मदद से पेड़ की मोटी शाखाओं और तने को कई हिस्सों में काटा, जबकि पुलिस ने मौके पर यातायात को नियंत्रित किया और वन विभाग की टीम ने पेड़ को सुरक्षित तरीके से हटाने में सहयोग किया।

सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा सीएम धामी के पांच साल का जश्न

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम में 20 हजार से अधिक लोगों की सहभागिता रही। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया एवं मुख्यमंत्री को उनके कार्याकाल के सफलतम 5 साल होने पर बधाई दी।

सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में देहरादून, हरिद्वार एवं टिहरी जनपदों के विभिन्न विभागों ने समन्वित रूप से सेवाएं प्रदान कीं। इंटीग्रेटेड एफर्टश (एकीकृत प्रयास) के तहत आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ मौके पर योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया गया। इससे नागरिकों को एक ही स्थान पर अनेक विभागों की सेवाएं प्राप्त हुईं।

कार्यक्रम में आयोजित विशाल स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गंभीर एवं पुरानी बीमारियों की 1009 मरीजों की जांच एवं उपचार किया गया। शिविर में

212 हड्डी रोगियों, 70 स्त्री रोगियों तथा 81 नेत्र, नाक एवं कान संबंधी रोगियों का परीक्षण एवं उपचार किया गया। इसके अतिरिक्त 13 बच्चों का टीकाकरण किया गया, 15 आयुष्मान कार्ड एवं 20 आभा कार्ड बनाए गए।

95 एक्स-रे एवं 70 रक्त जांचें की गईं। आयुष विभाग द्वारा 310 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क औषधियों का वितरण भी किया गया। इसके अतिरिक्त 23 लोगों के विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण किए गए।समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा वृद्धावस्था दिव्यांग सहित 75 लोगों की पेंशन मौके पर स्वीकृत की गई तथा 10 लोगों के यूडीआईडी कार्ड भी निर्गत किए गए। वही 280 दिव्यांगजनो को सहायक उपकरण वितरित किए गए। शिविर में कृषि, उद्यान, उद्योग, डेयरी, मत्स्य, रेशम, पशुपालन, लीड बैंक ने करीब 1200 से अधिक लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

सीएम धाम ने बड़ी योजनाओं की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को दी

देहरादून। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुआ एक आदेश सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला 5 करोड़ से बड़ी योजनाओं का है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के लिए नया गेटवे तैयार किया है। दरअसल इस आदेश के तहत बड़ी योजनाओं की डिटेल्ड रिपोर्ट जुटाने की जिम्मेदारी युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा को दी गई है, जिससे सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। धामी कैबिनेट में राजनीति के बड़े-बड़े धुरंधर मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद बड़ी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पर ही भरोसा जताया है, ये जिम्मेदारी पांच करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को लेकर है, जिस पर सभी मंत्रियों को डीटेल्ड रिपोर्ट सौरभ बहुगुणा को देनी है। खास बात यह है कि इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है, जिसने सियासी रूप से कई तरह की चर्चाएं शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंत्री सौरभ बहुगुणा को विशेष जिम्मेदारी देने वाला यह पत्र मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बसेड़ा की तरफ से सभी मंत्रियों के मुख्य, वरिष्ठ और निजी सचिवों को लिखा गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि विभिन्न विभागों में चल रही योजनाएं जिनकी लागत 5 करोड़ से ज्यादा है और जनहित में लाभकारी है, उन योजनाओं का विवरण और ब्रीफ नोट तैयार करके कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के अवलोकन के लिए भेजे जाएं। इसकी एक प्रति मुख्यमंत्री को भी

भेजने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से मंत्रियों के लिए जारी किए गए इस पत्र को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। सियासी रूप से कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे युवा मंत्री को ही इसके लिए क्यों चुना? यही नहीं मंत्रिमंडल में मौजूद वरिष्ठ मंत्री सीधे मुख्यमंत्री को बड़ी योजनाओं की जानकारी देने के बजाय युवा मंत्री को देने में खुद को कितना सहज महसूस करवा पाएंगे, ये भी एक सवाल हैं। इस मामले में कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि सीनियर मंत्रियों के लिए यह बेहद अजीब सी स्थिति हो जाएगी कि वह मुख्यमंत्री की जगह अपने जूनियर मंत्री को बड़ी योजनाओं की जानकारी दें और उसके बाद एक जूनियर मंत्री इन योजनाओं का अवलोकन करने के बाद इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दे।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा को सनातन की आस्था से कोई सरोकार नहीं : गरिमा मेहरा दसौनी

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में कथित चोरी के आरोपों ने भाजपा के तथाकथित हिंदुत्व की वास्तविकता को देश के सामने उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की धार्मिक भावनाओं का दोहन कर सत्ता तक पहुंचने वाली भाजपा का हिंदुत्व का मुखौटा अब पूरी तरह उतर चुका है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि पहले अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे, उसके बाद केदारनाथ में 230 किलो सोने के प्रकरण पर आज तक सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी और अब बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में कथित अनियमितताओं की खबरों ने करोड़ों सनातनियों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को न तो सनातन धर्म की मर्यादा से कोई सरोकार है और न ही मंदिरों की पवित्रता से। यदि मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से अर्पित दान और संपत्ति की सुरक्षा पर ही प्रश्नचिह्न लगने लगें, तो यह केवल आर्थिक अनियमितता का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास पर सीधा आघात है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार इन गंभीर आरोपों पर पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय उन्हें दबाने का प्रयास करती रही है। यही कारण है कि जनता का सरकार पर भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में निर्दोष है, तो उसे पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराकर सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

दसौनी ने कहा कि धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को अब देश की जनता जवाबदेह बनाएगी। करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ कथित विश्वासघात करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। आने वाले समय में भाजपा को अपने कर्मों का जवाब जनता की अदालत में देना ही होगा।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल ने रचा इतिहास

देहरादून। उत्तराखण्ड के संवैधानिक इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने 1,756 दिनों का कार्यकाल पूर्ण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह उपलब्धि एक संवैधानिक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड के विकास, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनके समर्पण का सशक्त प्रतीक है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 15 सितम्बर 2021 को उत्तराखण्ड के आठवें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। उनका कार्यकाल 4 वर्ष, 9 माह और 21 दिन का हो चुका है, जो राज्य गठन के बाद किसी भी राज्यपाल का सबसे लंबा कार्यकाल है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि सम्पूर्ण उत्तराखंड़ की है।

अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के साथ समाज के विविध वर्गों के बीच एक प्रेरक मार्गदर्शक, संवेदनशील संरक्षक और जनहितैषी व्यक्तित्व के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने राजभवन को जनसंवाद, नवाचार, शिक्षा, युवा प्रेरणा और सामाजिक जागरूकता का सक्रिय केन्द्र बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। राज्यपाल के रूप में उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व, सैनिक एवं पूर्व सैनिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जैव विविधता, स्वास्थ्य तथा सामाजिक समरसता जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दी। उन्होंने समय-समय पर विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों, युवाओं, सैनिक परिवारों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ संवाद स्थापित कर समाज के सर्वांगीण विकास को नई दिशा प्रदान की। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान, कौशल विकास तथा भारतीय ज्ञान परम्परा को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण पहल की।

उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा आज वैश्विक स्तर पर नई स्वीकार्यता प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय ही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसे ग्रन्थ समाज में सकारात्मक चिंतन, अनुसंधान और नवाचार की नई दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने इस महत्त्वपूर्ण कृति के प्रकाशन पर सभी रचनाकारों और आयोजकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने कहा कि माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह का जीवन राष्ट्रसेवा की प्रेरणादायी यात्रा है। भारतीय सेना में लगभग चार दशकों तक उत्कृष्ट सेवा देने के बाद उन्होंने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन भी उसी समर्पण, अनुशासन और दूरदृष्टि के साथ किया। देशभक्ति उनके परिवार की परम्परा रही है और यही संस्कार आगे चलकर उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व की आधारशिला बने। गुरमीत सिंह ने भारत की शक्ति व संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य किया है।

उन्होंने सैनिक पृष्ठभूमि से प्राप्त अनुशासन, समयबद्धता, पारदर्शिता और कर्तव्यनिष्ठा को राजभवन की कार्यशैली में भी प्रतिबिंबित किया। उत्तराखण्ड की प्राकृतिक धरोहर, हिमालय, नदियों, वन सम्पदा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए उन्होंने अनेक अवसरों पर जनजागरूकता का संदेश दिया। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आज विश्व एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मानवता का भविष्य एआई से सुरक्षित नहीं होगा। हमें एआई के साथ आरआई (राइटियस इंटेलिजेंस, ऋषि इंटेलिजेंस), एसआई (स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस) और सनातन इंटेलिजेंस की भी आवश्यकता है आइए अध्यात्म इंटेलिजेंस की ओर बढ़े।

प्रख्यात वैज्ञानिक एवं लेखक प्रो. अरुण तिवारी जी ने पुस्तक का विस्तृत परिचय देते हुए कहा कि एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस डोंट सर्च, फाइंड (प्रज्ञा, खोजें नहीं, समाधान पाएँ) पुस्तक विज्ञान और अध्यात्म के बीच संवाद स्थापित करने वाला एक वैचारिक सेतु है। उन्होंने बताया कि आधुनिक विज्ञान जहाँ बुद्धि की सीमाओं का अन्वेषण करता है, वहीं भारतीय अध्यात्म प्रज्ञा के माध्यम से अनन्त चेतना का अनुभव कराता है। यह ग्रन्थ दोनों धाराओं को एक सूत्र में पिरोने का अभिनव प्रयास है। कार्यक्रम का शुभारम्भ राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् एवं राष्ट्रगान के सामूहिक गायन के साथ हुआ, जिससे सम्पूर्ण सभागार राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति की दिव्य भावना से ओत-प्रोत हो उठा। इसके उपरान्त राज्यपाल के वित्त नियंत्रक डॉ. तृप्ति श्रीवास्तव जी ने सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए इस महत्त्वपूर्ण आयोजन की भूमिका प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा आज पुनः वैश्विक मंच पर अपनी सार्थकता सिद्ध कर रही है और ऐसे ग्रन्थ भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।

उत्तराखण्ड की पावन देवभूमि में आज ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के अद्वितीय समन्वय का एक ऐतिहासिक क्षण साकार हुआ। लोक भवन, देहरादून के सभागार में आयोजित गरिमामय समारोह में एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस डोंट सर्च, फाइंड (प्रज्ञा, खोजें नहीं, समाधान पाएँ) पुस्तक का भव्य लोकार्पण उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। समारोह में योग, आयुर्वेद, विज्ञान, शिक्षा और अध्यात्म जगत की अनेक विशिष्ट विभूतियों की गरिममयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर श्री रवि रमन जी, विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति, डीन, प्रोफेसर, गणमान्य अतिथि, नारी शक्ति की गरिमामयी उपस्थिति रही।

जिला कारागार पौड़ी में ''एक जेल-एक उत्पाद'' पहल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिला कारागार पौड़ी में ''एक जेल-एक उत्पाद'' पहल के तहत पिरूल क्राफ्ट आधारित तीन साप्ताहिक उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से जनकल्याण सेवा समिति, कोटद्वार द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को पिरूल से आकर्षक एवं उपयोगी हस्तशिल्प उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें रिहाई के बाद स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बंदियों द्वारा तैयार उत्पादों का अवलोकन कर उनके प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि पिरूल जैसे वन संसाधनों से तैयार उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है और इन्हें आजीविका का प्रभावी माध्यम बनाया जा सकता है। उन्होंने प्रशिक्षण को कौशल विकास के साथ उद्यमिता से जोड़ने पर जोर देते हुए वॉल हैंगिंग, बुके मेकिंग, सजावटी वस्तुएं, गृह उपयोगी सामग्री तथा अन्य नवाचार आधारित उत्पादों का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने तैयार उत्पादों की बायबैक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा उससे प्राप्त आय को बंदी कल्याण एवं पुनर्वास गतिविधियों में उपयोग करने की बात कही। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र और जेल प्रशासन की इस पहल को बंदियों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए भविष्य में भी ऐसे रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए।

सिंपल कार्डियो रेस्पिरेटरी रेस्क्यू टेक्निक समझने की जरूरत : डॉ. केपी जोशी

देहरादून। सिंपल कार्डियो रेस्पिरेटरी रेस्क्यू टेक्निक को सीपीआर कहा जाता है। यह एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस रुक जाए या दिल काम करना बंद कर दे (कार्डियक अरेस्ट)। यह दिमाग और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं।

चारधाम अस्पताल नेहरू कॉलोनी देहरादून के डॉ. केपी जोशी ने बताया की आज की जिन्दगी आधुनिकता की दौड़ में लगातार भाग रही है। प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों ही तरह से दुर्घटनाओं की संख्या बड़ रही है, साथ ही आधुनिक जीवन शैली सुविधाएं भी चुनौती पेश कर रही। परिणाम सडन डेथ या अचानक हृदय या सांस रुक जाने के कई मामले आ रहे। ये घर से लेकर स्कूल और सार्वजनिक

स्थानों पर हो रहे। जरूरत है जागरूक रहने व देश के सभी नागरिकों कक्षा 10 से अधिक के बच्चों को सिंपल कार्डियो रेस्पिरेटरी रेस्क्यू टेक्निक समझने व तत्काल प्रयोग में लाने की। रेस्क्यू टाइम बहुत शोर्ट होता है मैक्सिमम 3 मिनट। इसी पीरियड में डिसिशन लेकर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना होता है। आधुनिक युग में छोटे बच्चों में कई बीमारियां आ रही व जल्दी ऐज में बीपी शुगर मोटापा हार्ट की समस्या आ रही जो कि कुछ हद तक प्रीवेंटेबल है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन 2049 के लिए हमे स्ट्रॉग राष्ट्रीय चरित्र के लोगो की जरूरत होगी जिसका विकास बाल्यपन प्राइमरी स्कूलिंग से इंटरमीडिएट तक स्कूल में किया जाना है। उपरोक्त तीनो विषयों पर सोशल बलूनी स्कूल बाइपास रोड में टीचिंग अंडरस्टैंडिंग जागरूकता अभियान आरंभ होने जा रहा हैं, जो लगभग एक हजार छात्रों के साथ होगा।

कुंभ-2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने का दोहराया संकल्प

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में आयोजित पूज्य मोरारी बापू की श्रीराम कथा के समापन समारोह में श्रद्धालुओं को संबोधित करते

हुए कहा कि हरिद्वार की पावन धरा पर उन्हें अद्वितीय आध्यात्मिक सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने पूज्य मोरारी बापू का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोरारी बापू केवल श्रीराम कथा के वाचक नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के आदर्शों, विचारों और जीवन-दर्शन के जीवंत संवाहक हैं, जिन्होंने विश्वभर में भारतीय संस्कृति, सनातन दर्शन और अध्यात्म का संदेश पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब विश्व युद्ध, हिंसा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भारत की सनातन संस्कृति का ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का संदेश पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है और उत्तराखंड सरकार देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर तथा प्राचीन मंदिरों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं ने इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं और दो माह के भीतर ही 45 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार हेमकुंड साहिब यात्रा में डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं, जबकि कैलाश मानसरोवर यात्रा में 55000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जहाँ पहले पूरे वर्ष में सीमित संख्या में ही यात्रियों को भेजा जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जुलाई को कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रथम दल को रवाना करने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड में विकसित हो रहे बेहतर बुनियादी ढांचे, सुरक्षित यात्रा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने आगामी कुंभ-2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि कुंभ केवल आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक चेतना और सनातन संस्कृति का महापर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक गरिमा और सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि संतों के आशीर्वाद और जनसहभागिता से उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्य मंत्री सुनील सैनी, देशराज कर्णवाल, नितिन गौतम, अजीत चौधरी, शोभाराम प्रजापति, आदेश सैनी, जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

जनता की आवाज दबा रही है धामी सरकार : बुटोला

देहरादून। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने राजधानी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में वर्तमान राज्य सरकार और बद्री-केदार मंदिर समिति

के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी के मामले में तत्काल प्रभाव से उच्च न्यायालय के तीन सिटिंग जजों की विशेष समिति गठित कर निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए विधायक बुटोला अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने अत्यंत व्यथित मन से कहा:ष्मैं उस पवित्र और पावन भूमि का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ साक्षात भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम है, जहाँ गुरुओं की तपोभूमि श्री हेमकुंड साहिब स्थित है। आज हमारे इन पावन देवस्थानों और पवित्र मंदिरों में चढ़ावे की चोरी हो रही है। इस कुकृत्य से मेरा मन गहरे दुःख और पीड़ा से भरा है, और आज देश-विदेश के करोड़ों सनातनियों का मन भी पूरी तरह व्यथित है।ष्इसके साथ ही वर्तमान जांच प्रणाली और सरकार के रवैये पर कड़ा तंज कसते हुए उन्होंने यह शेर भी पढ़ा:ष्चोर भी तुम्हारा है सरकार का साया भी तुम्हारा है , तुम चोर को ईमानदार बता दो जाँच अधिकारी भी तुम्हारा है।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक बुटोला ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए निम्नलिखित मुख्य बिंदु मीडिया के सामने रखे।

सिटिंग जजों से जांच की मांग: सरकार की किसी भी विभागीय या स्थानीय जांच पर हमें भरोसा नहीं है। इस महाघोटाले का सच सामने लाने के लिए माननीय हाई कोर्ट के तीन सिटिंग जजों की कमेटी से ही समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए।

आस्था के साथ खिलवाड़ : बद्रीनाथ धाम में कथित दान चोरी का मामला केवल वित्तीय भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि देश-विदेश के करोड़ों सनातनियों की धार्मिक आस्था पर गहरा प्रहार है। सत्ता पक्ष में असंतोष का दावा भी किया उन्होंने कहा की सत्ता पक्ष के विधायकों की अपनी ही सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है।

पहाड़ की उपेक्षा: सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थानीय जनता बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आज भी तरस रही है।उन्होंने आगे कहा की एक छोटे से कर्मचारी को बलि का बकरा बनाकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है।

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए 24 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर में 200 हैण्डपम्प का निर्माण किये जाने हेतु 1.43 करोड़, रूडकी शहर सीवरेज हेतु 3.16 करोड तथा न्यू हरिद्वार मॉडल कालौनी और गोविन्दपुरी में क्षतिग्रस्त वितरण पाईप लाईन का प्रतिस्थापन हेतु 4.50 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित गढ़वाल एवं कुमायूं परिक्षेत्र में स्थित जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में मानकों के परीक्षण हेतु ऑटोमैटिक एनालाइजर सिस्टम आईएस 3025 पार्ट 82 - 83 क्रय किये जाने हेतु 2.54 करोड की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून की गडूल नदी (सौंग नदी की सहायक नदी) का पुनर्जीवन/ट्रीटमेंट के विभिन्न कार्य हेतु 6.02 करोड एवं जनपद उत्तरकाशी की कमल गंगा नदी का पुनर्जीवन/ट्रीटमेंट के विभिन्न कार्य हेतु 4.17 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में ओखलढूंगा झील के सुरक्षात्मक एवं विकास कार्य हेतु 74.38 लाख, जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता में बंगाली कालौनी के नव निर्मित दुर्गा मंदिर के सौन्दर्यकरण हेतु 56.51 लाख, विधानसभा क्षेत्र अल्मोडा के सेराघाट में मॉ मंगला भगवती माता मंदिर परिसर में धर्मशाला का निर्माण किये जाने हेतु 72.83 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार के न्याय पंचायत लालढांग के अन्तर्गत लाला ओम प्रकाश ज्ञानदीप कन्या इंटर कालेज की चाहर दीवारी के निर्माण हेतु 53.18 लाख स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

चारधाम परियोजना के पैकेज 2 एवं पैकेज 3 से संबंधित बैठक आयोजित

देहरादून। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रमेश कुमार सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में चारधाम परियोजना के पैकेज 2 एवं पैकेज 3 से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा चारधाम परियोजना के पैकेज 2 एवं पैकेज 3 से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण, बस। स्तर पर लंबित मुआवजा वितरण, मध्यस्थता वादों, स्वामित्व विवादों तथा अन्य प्रासंगिक विषयों की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। प्रमुख सचिव ने चारधाम परियोजना के पैकेज 2 एवं पैकेज-3 के अन्तर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सम्बन्धित भूमि का कब्जा कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को अधिकतम एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि निर्धारित समयावधि के भीतर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण न किए जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग श्री पंकज कुमार पाण्डेय सहित अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्रीमती कल्याणी, श्रीमती मीनाक्षी जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, अपर जिलाधिकारी, चमोली तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

सीएम पुष्कर सिंह धामी का रिकॉर्ड कार्यकाल

उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में यह वर्ष 2026 एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार पाँच वर्षों तक राज्य का नेतृत्व करते हुए उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिसे लंबे समय तक अजेय माना गया है। राज्य गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त (एन. डी.) तिवारी का कार्यकाल उत्तराखंड के सबसे लंबे और स्थिर शासन के रूप में जाना जाता था। लेकिन जुलाई 2026 में पुष्कर सिंह धामी ने इस रिकॉर्ड को पार करते हुए राज्य के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का नया इतिहास रच दिया। एनडी तिवारी 1831 दिन तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एनडी तिवारी और पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के बीच कितने बड़े चेहरे आये जिसमें हरीश रावत और मेजर जनरल रिटायर्ड बीसी खण्डूड़ी भी शामिल है लेकिन कोई उस लकीर को पार नहीं कर पाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत थोड़े करीब जरूर पहुंचे थे पर वो भी अंतिम साल में बदल दिये गये थे।

पुष्कर सिंह धामी की ये उपलब्धि सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड में नेतृत्व की निरंतरता, प्रशासनिक स्थिरता और दीर्घकालिक नीति निर्माण की दृष्टि से भी एक उल्लेखनीय घटना है। एक लम्बे समय बाद ठहराव आया है और ठहराव सुखद होते हैं। नीतियां बनाना, विकास करना, शासन करना, नौकरशाही को समझना ये सब आसान और प्रदेश हित में हो जाता है। दरअसल किसी भी सरकार का मूल्यांकन केवल उसके कार्यकाल की अवधि से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों, नीतियों और उनके प्रभाव से किया जाता है और धामी ने कई निर्णय ऐसे लिये हैं जो प्रदेश में पहली बार लिये गये हैं और जिनकी गूंज देशभर में रही है।

पुष्कर सिंह धामी अब तक प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और जुलाई 2021 में जिस परिस्थिति में उनको लाया गया था वो आसान नहीं था। त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल पर भाजपा बात करना चाहती थी और तीरथ सिंह रावत के अजीब बयान भाजपा की मुश्किलों को लगातार बढ़ा रहे थे। समय कम था। भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एक चुना हुआ विधायक और मजबूत नेता चाहिए था। ऐसे समय में भाजपा को पुष्कर सिंह धामी की याद आयी थी। पुष्कर सिंह धामी ने भी खुद को साबित करके दिखाया। हालांकि वो 2022 में खुद चुनाव हार गये लेकिन भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बनी। हाईकमान ने उन पर अपना भरोसा जताया और हारने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया।

पुष्कर सिंह धामी के पाँच वर्षों का मूल्यांकन संतुलित दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है। यूसीसी, नकल विरोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति, कठोर धर्मांतरण कानून और अवैध मजारों पर बुलडोजर कई ऐसे मुद्दें है जिन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हो सकते हैं। बड़ी चर्चाऐं हो सकती हैं लेकिन इतना जरूर है कि पुष्कर सिंह धामी जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हाईकमान उनके साथ है। ये लाभ ही उनके राजनीतिक कद को बड़ा बनाता है। अब उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा है तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आने वाले वर्षों में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अपेक्षित परिणाम भी देना है और प्रदेश के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी जीत भी अपनी पार्टी को दिलानी है। विकास पर तो खुद प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है लेकिन इस दशक को और एतिहासिक बनाना ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही करना होगा।

श्रीलंका के अधिकारियों को भाया उत्तराखण्ड का आपदा प्रबंधन मॉडल

देहरादून। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) के तत्वावधान में आपदा प्रबंधन विषय पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीलंका के 40 सदस्यीय सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखण्ड में विकसित आपदा प्रबंधन प्रणाली, आधुनिक तकनीकों, पूर्व चेतावनी तंत्र, भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली तथा सामुदायिक सहभागिता आधारित पहलों का विस्तृत अध्ययन किया।

यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) श्री प्रकाश चंद्र ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड जैसे संवेदनशील राज्य में आपदा प्रबंधन केवल आपदा के समय राहत एवं बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, संस्थागत समन्वय, क्षमता निर्माण तथा आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) एवं डीआईजी श्री राजकुमार नेगी ने प्रतिभागियों को बताया कि उत्तराखण्ड में आपदाओं के दौरान त्वरित एवं समन्वित राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत तंत्र विकसित किया गया है। उन्होंने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) एवं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों (डीईओसी) की कार्यप्रणाली, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस), बहु-स्रोत पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा अलर्ट जारी करने की प्रक्रिया तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित निर्णय सहायता प्रणालियों की विस्तार से जानकारी दी।

मौसम विशेषज्ञ डॉ. पूजा राणा ने प्रतिनिधिमंडल को राज्य की मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) उपग्रह आधारित अवलोकन प्रणाली, डॉप्लर वेदर रडार, स्वचालित मौसम केंद्र (एडब्ल्यूएस), स्वचालित वर्षामापी यंत्र (एआरजी) तथा अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से लगातार मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। इन आंकड़ों का रियल-टाइम विश्लेषण कर अल्पकालिक, मध्यम अवधि एवं प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं। उत्तराखण्ड भू-स्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (यूएलएमएमसी) के निदेशक डॉ. शांतनु सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को राज्य में भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण के लिए किए जा रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संवेदनशील ढलानों की विस्तृत भू-वैज्ञानिक एवं भू-तकनीकी जांच, रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस आधारित मानचित्रण, ड्रोन सर्वेक्षण, ढलानों की सतत निगरानी, वर्षा आधारित भूस्खलन विश्लेषण तथा जोखिम आकलन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन अध्ययनों के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां स्थायी उपचारात्मक उपाय, ढलान स्थिरीकरण, जल निकासी सुधार तथा आवश्यक इंजीनियरिंग कार्य किए जाते हैं। श्रीलंका में भी अत्यधिक वर्षा एवं भूस्खलन की घटनाएं सामान्य होने के कारण प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखण्ड की इन व्यवस्थाओं में विशेष रुचि दिखाई। इस अवसर पर एनसीजीजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ए.पी. सिंह, डॉ. एमके भण्डारी, यूएसडीएमए के आपदा जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ डॉ. पीडी माथुर, श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल में सुश्री हेवाजुलिगे मधुपानी अप्सरा चित्रानाली पियासेना, श्री बामुनु अरच्चिगे चमरा प्रेमनाथ बामुनु अरच्ची तथा श्री एडम लेब्बे मोहम्मद अजमी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस प्रकार के अध्ययन कार्यक्रम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के प्रभावी माध्यम हैं। विभिन्न देशों के अनुभवों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान से संस्थागत दक्षता बढ़ती है तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अधिक समन्वित और प्रभावी दृष्टिकोण विकसित होता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में विकसित मॉडल और अनुभव अन्य देशों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, वहीं वैश्विक अनुभवों से सीखकर राज्य की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

एनसीजीजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ए.पी. सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सुशासन, नीतिगत सुधार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रमुख संस्थान है। उन्होंने बताया कि संस्थान अब तक 52 देशों के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित कर चुका है तथा हजारों अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है। श्रीलंका सरकार के साथ हुए सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विषय पर आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत यह अध्ययन भ्रमण आयोजित किया गया।

प्रस्तावित मास्टर प्लान-2041 पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की जनसुनवाई

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकसित एवं सुनियोजित उत्तराखंड के विजन के अनुरूप एमडीडीए द्वारा प्रस्तावित मास्टर प्लान-2041 पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की जनसुनवाई प्रारंभ हो गई।

पहले दिन माता मंदिर रोड स्थित शकुन स्पोर्ट्स एकेडमी में सेक्टर-1 से संबंधित आपत्तियों पर सुनवाई की गई, जिसमें 18 आपत्तियों एवं सुझावों पर विस्तार से विचार किया गया। नागरिकों ने भूमि उपयोग, विकास योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए एक व्यवहारिक, संतुलित और जनहितैषी मास्टर प्लान तैयार करना है। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी सुझावों का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा तथा जो सुझाव व्यवहारिक एवं जनहित में होंगे, उन्हें आवश्यकतानुसार मास्टर प्लान-2041 में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

सतपुली, स्यूंसी झील निर्माण से पैदा होंगे आजीविका के नए अवसर : महाराज

बीरोंखाल (पौड़ी)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिख रही है। प्रदेश में कई बड़ी योजनाएं आगे बढ़ा रही है। सतपुली झील और स्यूंसी झील के निर्माण से चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से एक नये डेस्टीनेशन के रुप में विकसित हो रहा है। उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री एवं चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने क्षेत्र भ्रमण के पांचवें दिन बुधवार को सतपुली मण्डल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुल्हाड में 123.18 लाख की धनराशि से बनने वाली 2 किमी. कुल्हाड बैण्ड से किनसूर-भरवाडी-कैण्डुल- डलगांव-उमन-किनसूर मोटर मार्ग के शिलान्यास के अवसर पर कही। इस दौरान उन्होंने आम जनता की समस्याओं एवं शिकायतों को सुनने के साथ-साथ सरकार द्वारा चौबट्टाखाल विधानसभा में किये जा रहे विकास कार्यों से भी अवगत करवाया। कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल श्री महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, जमरानी बांध और सौंग बांध जैसी बड़ी परियोजना पर तेज से काम चल रहा है। सतपुली में करीब 56 करोड़ रुपये की लागत से 750 मीटर लंबी झील बनाई जा रही है। झील बनने से वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और यहां पैराग्लाइडिंग भी शुरू की जाएगी। जबकि बीरोंखाल विकासखंड में 123.41 करोड़ की लागत से बनने वाले स्यूंसी झील (बैराज) परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे और जल संकट दूर होगा। यह बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ जल संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने सशक्त मंडल और सशक्त संगठन के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का भी अनुरोध किया। इस अवसर पर भाजपा युवा नेता सुयश रावत, जिलाध्यक्ष कमल किशोर, मण्डल अध्यक्ष सरवेन्द्र, जिला मंत्री बृजमोहन, बूथ अध्यक्ष दिगम्बर, सुरेन्द्र सिंह, गबर सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित, अनिता देवी, सुरेश कुमार, एसडीएम रेखा आर्य आदि कई अधिकारी भी मौजूद थे।

29 अगस्त को गौलापार में सीएम करेगे खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास

देहरादून। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2025 के नेशनल मेडलिस्ट बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब देने के लिए विभाग को आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी के साथ ही लेगेसी के तहत 23 एकेडमी जोकि अस्थायी तौर पर संचालित की जा रही हैं को स्थायी तौर पर संचालित करने हेतु पदों को सृजित करने की आवश्यकता के संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 243 नेशनल मेडलिस्ट बच्चों को लेगेसी के तहत एकेडमी, खेल विश्वविद्यालय तथा अन्य विभागों में आउट ऑफ टर्न जॉब के माध्यम से समायोजित करने हेतु भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि आउट ऑफ टर्न के माध्यम से अन्य विभागों में सेवा प्रदान करने वाले बच्चों को मूल विभाग में ही डेप्यूटेशन के तहत तैनाती किये जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। मंत्री ने कहा कि 29 अगस्त 2026 राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गौलापार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जायेगा इसके लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को तीव्र गति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। मंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प उत्तराखण्ड को एक बेहतर खेल भूमि बनाना है। मंत्री ने कहा कि आज की बैठक में खेल नीति पर भी विस्तृत चर्चा की गई है जिसमें पूर्व की खेल नीति की कमियों को दूर करके नई नीति को भारत सरकार की खेल नीति के अनुरूप तैयार करने के दिशा निर्देश दिये गये हैं इसमें पारंपरिक खेलों को स्थान देने के साथ ही पैरा एथिलिटस तथा बौना एथिलिट के लिए समूचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि खेल नीति पर खिलाड़ियों के साथ-साथ आमजन से सुझाव मांगे जायेंगे जिसमें बेहतर सुझाव को खेल नीति का हिस्सा बनाने के साथ ही संबंधित को सम्मानित किया जायेगा। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल, अमित सिन्हा, निदेशक खेल, दीप्ति सिंह, महाराणा प्रताप खेल परिसर के प्रिसिंपल राजेश ममगाईं संयुक्त निदेशक खेल, अजय अग्रवाल तथा अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति ने की राज्यपाल से मुलाकात

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से लोक भवन में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के कुलपति प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी ने शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान कुलपति ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों, चल रही अनुसंधान परियोजनाओं तथा भविष्य की कार्ययोजना (रोडमैप) से अवगत कराया। उन्होंने विश्वविद्यालय में विकसित की जा रही अवस्थापना सुविधाओं एवं संस्थागत विकास से संबंधित कार्यों की भी जानकारी दी। कुलपति ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक ''आयुर्गाथा'' और एक लघु फिल्म राज्यपाल को भेंट की। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन एवं समृद्ध ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने विश्वविद्यालय से अपेक्षा की कि वह वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान, नवाचार, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर नई दिशा प्रदान करे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अवस्थापना सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा शोध एवं नवाचार आधारित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

उत्तराखण्ड दौरे पर आए नीति आयोग के सदस्य, मुख्य सचिव ने किया स्वागत

देहरादून । मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय स्थित अपने सभागार में उत्तराखण्ड दौरे पर आए नीति आयोग के सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास एवं उनकी टीम का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बैठक के दौरान राज्य की ओर से प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने राज्य की प्रगति एवं सलाहकार एवं कार्यक्रम निदेशक नीति आयोग डॉ. सोनिया पंत ने प्रदेश की मुख्य उपलब्धियों और आर्थिक रूपरेखा पर प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव ने सदस्य नीति आयोग एवं उनकी टीम का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड ने राज्य गठन के बाद आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पर्यटन और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड कई संकेतकों पर अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। राज्य ने सतत् विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष रैंक हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल बनाने एवं नागरिक-अनुकूल नियामक प्रक्रियाओं के जरिए जीवन-यापन को आसान बनाने की दिशा में कार्य हुआ है। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में दूर-दराज के क्षेत्रों में किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एक चुनौती बनी हुई है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में नीति आयोग से लगातार और असरदार तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। हिमालयी क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी क्षेत्रीय समस्याओं, क्लिनिकल बेस्ट प्रैक्टिस, क्षमता निर्माण, टेलीमेडिसिन और आपातकालीन देखभाल पर स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एम्स और ऐसे ही अन्य सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को नॉलेज पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सदस्य नीति आयोग डॉ. एम. श्रीनिवास ने कहा कि उत्तराखण्ड विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़े आउटकम इंडीकेटर्स और एसडीजी लक्ष्यों पर और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड की स्थिति मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर आदि में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, परन्तु इनमें और सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और टीबी ट्रीटमेंट की दिशा में प्रयास बढ़ाए जाने पर जोर देते हुए उन्होंने प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किए जाने की बात कही। कहा कि आपातकालीन और ट्रॉमा देखभाल सेवाओं को मजबूत बनाया जाए।

11 जुलाई से सजेगा 'लोक संवर्धन पर्व' जुटेंगे देशभर के अल्पसंख्यक हुनरमंद

देहरादून। समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन होने जा रहा है। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की

'प्रधानमंत्री विकास योजना' के अंतर्गत आगामी 11 से 15 जुलाई तक परेड ग्राउंड में पांच दिवसीय उत्तरी क्षेत्रीय 'लोक संवर्धन पर्व' का भव्य आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम के तत्वाधान में होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के छठे इवेंट का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री खजान दास करेंगे। इस ग्रांड इवेंट में उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक कारीगर अपने स्वदेशी और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन व विपणन (बिक्री) करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस श्रृंखला का छठा आयोजन पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है। इससे पूर्व दिल्ली के राजघाट, दिल्ली हाट, आईएनए के साथ जम्मू कश्मीर तथा कोच्चि (करेल) में इसका सफल आयोजन हो चुका है।

बुधवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि इस प्रतिष्ठित आयोजन के 6वें इवेंट हेतु उत्तराखंड का चयन होना गर्व की बात है, इसलिए भव्यता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मानसून सीजन को देखते हुए उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर वॉटरप्रूफ टेंट, जल निकासी, पुख्ता सुरक्षा और फायर क्लीयरेंस की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से 'बायर-सेलर मीट' और उद्यमियों के बीच संवाद सत्र का आयोजन कराने के साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े एनजीओ को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर निर्बाध बिजली, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने और नगर निगम को शौचालयों की सफाई के साथ-साथ डेंगू के खतरे को देखते हुए फॉगिंग व दवाओं का नियमित छिड़काव के निर्देश दिए। पुलिस विभाग को सुचारू यातायात प्लान और आवश्यक सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य के लोक उत्सव 'हरेला' के पावन अवसर पर आयोजित हो रहे इस पर्व में कुल 160 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें से 130 स्टॉल शिल्पकारों (कारीगरों) के लिए और 30 स्टॉल पारंपरिक व्यंजनों (फूड कोर्ट) के लिए होंगे। स्थानीय हुनर को बढ़ावा देने के लिए 40 प्रतिशत स्टॉल उत्तराखंड के कारीगरों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

मंत्रालय के मानकों के अनुसार, महिला और युवा कारीगरों, पहली बार भाग ले रहे हुनरमंदों, लुप्त हो रही कलाओं के जानकारों और छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी) के लाभार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। खास बात यह है कि चयनित कारीगरों को ये स्टॉल पूरी तरह नि:शुल्क आवंटित किए जाएंगे।

यह पांच दिवसीय पर्व 11 जुलाई से प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। मेले को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी लोक संस्कृति और कला का रंग बिखेरेंगे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश चन्द्र तिवारी, सीओ पुलिस जगदीश चन्द्र पंत, महाप्रबंधक अल्पसंख्यक कल्याण निगम डॉ शाहिद सिद्दीकी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय निदेशक जगदीश कुमार, डीजीएम एनएमडीएफसी पीएस पानवीकर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में संभावित प्रभाव का पूर्व आकलन किया जाएगा

देहरादून। राज्य के सभी प्रमुख बांधों एवं बैराजों को प्रतिदिन सुबह 8 बजे तथा शाम 8 बजे अपने जलाशयों के जलस्तर, इनफ्लो, आउटफ्लो तथा डिस्चार्ज से संबंधित अद्यतन जानकारी अनिवार्य रूप

से यूएसडीएमए को उपलब्ध करानी होगी। मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बुध वार को यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों एवं जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों को मानसून के दौरान बेहतर समन्वय तथा निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी भी बांध अथवा बैराज से पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित हो तो इसकी पूर्व सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र तथा संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। सूचना में यह भी उल्लेख किया जाए कि छोड़ा गया पानी कितने समय में किन-किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में नदी के जलस्तर में कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा इससे संभावित प्रभाव क्या होंगे ताकि समय रहते संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा सकें। सचिव श्री सुमन ने सभी परियोजनाओं को निर्देशित किया कि पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत स्थापित नदी जलस्तर सेंसरों एवं डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों को एपीआई के माध्यम से रियल टाइम में यूएसडीएमए के साथ साझा किया जाए। बैठक में सभी जल विद्युत परियोजनाओं एवं बांध प्रबंधन को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापित ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन तथा अर्ली वार्निंग सिस्टम का विस्तार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विशेष रूप से टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को अपने क्षेत्र में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 25 करने के निर्देश दिए ताकि मौसम संबंधी आंकड़े अधिक सटीक एवं व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि एक ही नदी तंत्र में स्थित अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम बांधों तथा बैराजों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। सभी परियोजनाएं आपस में नियमित रूप से जलस्तर, वर्षा, डिस्चार्ज तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान करें, जिससे किसी भी आकस्मिक स्थिति में समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-प्रशासन श्री प्रकाश चंद्र ने कहा कि सभी परियोजनाओं में स्थापित डिस्चार्ज सायरन, चेतावनी उपकरणों तथा विभिन्न सेंसरों की नियमित टेस्टिंग की जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान तकनीकी उपकरणों की कार्यशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी को तत्काल दूर किया जाए। संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दिनेश कुमार पुनेठा ने कहा कि बाढ़ संभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित की जाए। जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए तथा ऐसी सभी व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखी जाएं, जिनसे भारी वर्षा के दौरान आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए।

हरेला पर्व पर उद्यान विभाग करेगा 11 लाख पौधों का रोपण : कृषि मंत्री गणेश जोशी

देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को कैंप कार्यालय में आगामी 16 जुलाई को मनाए जाने वाले हरेला पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को प्रदेशभर

में बड़े स्तर पर फलदार, सगंध एवं औषधीय पौधों का रोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरेला पर्व केवल पौधारोपण का पर्व नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का जन अभियान है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे पौधों का चयन करने के निर्देश दिए, जो जल स्रोतों के पुनर्जीवन, भू-जल संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक हों। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को वर्षाकाल में नवीनतम रंगीन फल प्रजातियों के आम, अमरूद, लीची, अनार, नींबू, माल्टा, कटहल सहित अन्य फलदार पौधों का व्यापक स्तर पर रोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पौधों के वितरण एवं रोपण की सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस वर्ष हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेशभर में उद्यान विभाग द्वारा 11 लाख फलदार, सगंध एवं औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक लाख चाय के पौधे भी रोपित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हरेला पर्व पर उद्यान विभाग द्वारा 9 लाख से अधिक फलदार पौधों का सफलतापूर्वक रोपण किया गया था, जबकि इस वर्ष लक्ष्य को और बढ़ाते हुए व्यापक जनभागीदारी के साथ अभियान संचालित किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केवल पौधारोपण तक ही सीमित न रहें, बल्कि लगाए गए पौधों के संरक्षण, नियमित देखरेख और उनकी शत-प्रतिशत जीवित रहने की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य सार्थक रूप से पूरा हो सके। बैठक के दौरान विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को इस वर्ष वर्षाकालीन में हरेला पर्व / नि:शुल्क फल पौध रोपण योजनान्तर्गत फलदार पौधों के आवंटन की सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष हरेला पर्व पर उद्यान विभाग द्वारा 9 लाख से अधिक फलदार पौधों का रोपण किया गया।

बहुत अच्छे वॉयलेन वादक थे चेतन आनंद

नई दिल्ली। चेतन आनंद को उनके पिता पिशोरी लाल आनंद ने पढ़ाई करने लंदन भेजा था। पिता चाहते थे कि चेतन इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करें। चेतन ने लंदन की एक यूनिवर्सिटी से एमए किया था। उसके बाद कुछ वक्त तक उन्होंने बीबीसी में भी काम किया। पर चूंकि वो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा क्लियर नहीं कर सके तो भारत वापस लौट आए। भारत आने के बाद चेतन आनंद ने 1940 में दून स्कूल में हिंदी टीचर की हैसियत से नौकरी करना शुरू कर दिया। चेतन वहां सिर्फ हिंदी टीचर ही नहीं थे। उन्होंने थिएटर व ड्रैमेटिक्स में भी स्टूडेंट्स के साथ रहकर काफी काम किया था। ये बात शायद कम लोग जानते होंगे कि चेतन आनंद बहुत अच्छे वॉयलेन वादक थे। 1943 में चेतन आनंद ने एक बंगाली ईसाई लड़की से शादी कर ली। उनका नाम था उमा चटर्जी। चेतन और उमा की जान-पहचान पहले से थी। उमा के पिता, जिनका नाम ज्ञानेश चन्द्र चटर्जी लॉ कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। जब उमा की शादी चेतन से हो गई तो वो हो गई उमा आनंद। देव आनंद की पत्नी मोना सिंघा उर्फ कल्पना कार्तिक उमा आनंद की रिश्तेदार थी। मोना सिंघा उमा आनंद की नानी के भाई की बेटी थी। शादी के बाद पत्नी उमा संग चेतन आनंद दून स्कूल में ही रहने लगे। मगर इसी बीच उनके भीतर फिल्म लेखन की कामना जाग गई। वो फिल्मों की स्क्रिप्ट्स लिखने लगे और उन्हें बम्बई भेजने लगे। फिल्मी दुनिया से जुड़ने की बेचौनी चेतन आनंद के भीतर इतनी ज्यादा होने लगी कि एक दिन वो बम्बई आ ही गए। कुछ दिन बाद चेतन के छोटे भाई देव आनंद भी हीरो बनने की तमन्ना लिए बंबई आ गए। मगर चेतन आनंद फिर से देहरादून लौट गए। और आखिरकार 1944 में चेतन आनंद नौकरी से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी संग पूरी तरह से बम्बई में सेटल्ड हो गए। उन्होंने पाली हिल में एक बंगला किराए पर ले लिया था। बाद में देव आनंद भी उनके साथ ही रहने आ गए थे। बम्बई में चेतन आनंद की दोस्ती कई क्रिएटिव लोगों से हुई। मोहन सैगल, जोहरा सहगल, बलराज साहनी, पंडित रविशंकर व कई और लोगों का व चेतन आनंद का एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप का अधिकतर समय चेतन आनंद के उस किराए के बंगले में ही गुजरता था। अधिकतर लोग इंडियन पीपल्स थिएटर असोसिएशन, यानि इप्टा से जुड़े थे। ये वही वक्त भी था जब चेतन आनंद ने सम्राट अशोक के जीवन पर एक कहानी लिखी थी। नामी फिल्मकार फणी मजूमदार को वो कहानी बहुत पसंद आई थी। उन्होंने चेतन आनंद की उस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। उस फिल्म में फणी मजूमदार ने चेतन आनंद व नर्गिस को उस फिल्म में लिया था। मगर वो फिल्म कभी रिलीज ना हो सकी। इसी दौरान चेतन आनंद ने पत्रकार-लेखक हयातुल्ला अंसारी की एक कहानी पर फिल्म बनाने का विचार बनाया। मशहूर लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने उस कहानी को फिल्म की स्क्रिप्ट में बदला। और तय हुआ कि चेतन आनंद उस कहानी पर श्नीचा नगरश नाम से फिल्म बनाएंगे। और फिल्म के हीरो-हीरोइन होंगे बलराज साहनी व उनकी पत्नी दमयन्ती।बलराज साहनी की की ऑटोबायोग्राफी ष्मेरी फिल्मी आत्मकथाष् बलराज साहनी जी ने लिखा है कि उस जमाने में अंग्रेज सरकार की तरफ से फिल्म बनाने के लाइसेंस जारी किए जाते थे। वो भी बहुत कम लोगों को। रफीक अनवर नामक एक शख्स के पास भी फिल्म बनाने का लाइसेंस था। और रफीक अनवर की जान-पहचान बलराज साहनी, उनकी पत्नी व चेतन आनंद से भी थी। चेतन आनंद ने जब रफीक अनवर के लाइसेंस पर नीचा नगर फिल्म बनाने की बात की तो रफीक अनवर ने शर्त रख दी कि फिल्म के हीरो वो होंगे। चेतन आनंद को ना चाहते हुए भी रफीक अनवर की बात माननी पड़ी। इस तरह बलराज साहनी के हाथ से नीचा नगर निकल गई। बलराज साहनी फिल्म से हटे तो उनकी पत्नी दमयन्ती ने भी फिल्म छोड़ दी। तब चेतन आनंद ने अपने दोस्त की बहन उमा कश्यप को अपनी फिल्म में काम करने के लिए मनाया। उमा कश्यप को उन्होंने नाम दिया कामिनी कौशल। और ये नाम उन्हें इसलिए दिया या था क्योंकि नीचा नगर में चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद भी काम कर रही थी। चेतन ने जोहरा सहगल को भी नीचा नगर में एक रोल दिया। यूं जोहरा सहगल की शुरुआत भी इसी फिल्म से हुई। पंडित रविशंकर ने इस फिल्म के संगीत का जिम्मा संभाला। नीचा नगर बनी। मगर भारत में कभी ना रिलीज हो सकी। हालांकि भारत की तरफ से इसे कान्स फिल्म फेस्टिवल में जरूर दिखाया गया। और नीचा नगर ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्री अवॉर्ड अपने नाम किया था। अब इसी अवॉर्ड को कान्स फिल्म फेस्टिवल वाले गोल्डन पाम कहने लगे हैं। 1980 के दशक में नीचा नगर को दूरदर्शन पर दिखाया गया था। मगर इस फिल्म के भारत में रिलीज ना होने की वजह से चेतन आनंद बहुत दुखी हुए थे। बताया जाता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ था, इसलिए ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी थी।साथियों आज चेतन आनंद की पुण्यतिथि है। साल 1997 में आज ही के दिन, 06 जुलाई को चेतन आनंद का देहांत हुआ था। कघ्स्सा टीवी चेतन आनंद को बहुत सम्मान से याद करते हुए उन्हें सैल्यूट करता है।

धर्मेंद्रकी इस एक सीख ने पूरे देओल फैमली को बांध रखा है, हेमा मालिनी ने खोला ये राज

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने एक

हालिया इंटरव्यू में अपने परिवार और दिग्गज अभिनेता ध मेंद्र को लेकर कई दिल छू लेने वाली बातें शेयर की हैं। हेमा ने बताया कि धरम जी हमेशा परिवार को सबसे ऊपर रखते थे और उनकी यही सीख आज भी पूरे परिवार को एक साथ बांधकर रखती है। उन्होंने बताया कि धरम जी अक्सर कहा करते थे, बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। आज के दौर में मिल-जुलकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे अक्सर अपनी-अपनी राह चुनकर अलग हो जाते हैं।ष

क्या थी धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा?

जब इंटरव्यू में हेमा मालिनी से पूछा गया कि ही-मैन ध मेंद्र की आखिरी इच्छा क्या थी, तो उन्होंने बेहद भावुक होकर इसका जवाब दिया। हेमा ने कहा, उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि सब लोग परिवार के साथ रहें। उन्होंने कहा था कि उन सभी के साथ मिलकर रहो। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन परिवार को सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए।

सनी और बॉबी देओल के रिश्ते पर क्या बोलीं हेमा?

धर्मेंद्र की पहली शादी से हुए बच्चों (सनी देओल और बॉबी देओल) के साथ अपने रिश्तों पर बात करते हुए हेमा मालिनी ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा, वे दोनों बहुत प्यारे और अच्छे हैं। हम सब हमेशा साथ रहते हैं। हम अपने रिश्ते का कोई दिखावा या पब्लिसिटी नहीं करते, लेकिन अंदर से हम सब एक हैं। हम सब एकजुट हैं और एक बहुत खुशहाल परिवार हैं।

फैंस का दिल जीतने वाले इंसान थे धर्मेंद्र

इंटरव्यू के दौरान हेमा ने धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए उन्हें एक बेहतरीन इंसान, एक बहुत प्यार करने वाले पिता और एक प्यारे नाना बताया। उन्होंने याद किया कि धर्मेंद्र अपने फैंस का कितना सम्मान करते थे। हेमा ने कहा, अगर कोई उनके साथ फोटो खिंचवाने आता था, तो वह कहते थे कि उन्हें अंदर बुलाओ। वह हर किसी से मिलते थे और सबको खाना खिलाते थे। उन्हें लोगों से मिलना-जुलना बेहद पसंद था। हेमा ने भावुक होते हुए कहा कि आज बच्चे उन्हें कितना याद कर रहे हैं, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर खत्म, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ऐलान

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी सीजफायर के खत्म होने का

ऐलान किया है. तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो की बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया. इससे समूचे खाड़ी क्षेत्र में फिर से अशांति की आशंका बढ़ गई है. इस बीच ईरान ने कहा है कि उसने अपने क्षेत्र में अमेरिकी हमले के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में कई अमेरिका ठिकानों पर हमले किए हैं

अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर अब खत्म हो चुका है. नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने ईरान पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाया और कहा कि अब तेहरान के साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा– मुझे लगता है कि ईरान के साथ हुआ समझौता अब खत्म हो चुका है. उनके साथ बातचीत करना सिर्फ समय बर्बाद करना है. उन्होंने ईरान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तेहरान ने समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं किया.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे झूठे हैं हमने एक समझौता किया था. उस पर सभी सहमत थे. साफ तय हुआ था कि परमाणु हथियार नहीं होंगे. लेकिन समझौते के बाद वे बाहर जाकर मीडिया से कहते रहे कि इस मुद्दे पर हमारी कभी कोई बातचीत ही नहीं हुई उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है. वे पूरी तरह सनक चुके हैं ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव फिर तेजी से बढ़ गया है. ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. ईरान का कहना है कि ये हमले उसके होर्मोजगान प्रांत और महशहर बंदरगाह पर हुई अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए.ईरानी दावों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया. बहरीन और कुवैत में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजने लगे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. दोनों देशों के सुरक्षा तंत्र को तत्काल सक्रिय कर दिया गया.

अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में एक अस्थायी समझौता हुआ था, जिसके तहत संघर्ष रोकने और परमाणु कार्यक्रम समेत कई विवादित मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी. हालांकि अब ट्रंप के ताजा बयान से साफ हो गया है कि वॉशिंगटन इस समझौते को समाप्त मान रहा है.

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की घोषणा के बाद पश्चिम एशिया में हालात और गंभीर हो सकते हैं. पहले से ही मिसाइल हमलों, ड्रोन हमलों और समुद्री सुरक्षा को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है. ऐसे में यदि दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई फिर तेज होती है, तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है.

सोशल मीडिया पर प्रचलित विभिन्न भ्रामक धारणाओं पर साक्ष्य-आधारित तथ्य प्रस्तुत किए

नई दिल्ली। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम भारत के ऊर्जा परिवर्तन तथा जैव ईंधन रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, किसानों को समर्थन प्रदान करना तथा पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है। यह कार्यक्रम देश में उत्पादित नवीकरणीय ईंधन के अधिकाधिक उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत एथेनॉल सम्मिश्रण वर्ष 2013-14 के 1.5 प्रतिशत से भी कम से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 20 प्रतिशत तक पहुंच गया है। भारत ने 20 प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया। एथेनॉल की खरीद एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में लगभग 38 करोड़ लीटर थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1,200 करोड़ लीटर (अनुमानित) से अधिक हो गई। उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 में रही 421 करोड़ लीटर से लगभग पांच गुना बढ़कर वर्ष 2026 में लगभग 2,000 करोड़ लीटर हो गई है। इस विस्तार से कच्चे तेल के आयात में कमी आई है तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही, इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है तथा नए बाजार अवसरों के माध्यम से किसानों की आय को भी सुदृढ़ किया गया है।

भारत अपनी आवश्यकता के लगभग 88.5 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है। यही एक तथ्य स्पष्ट कर देता है कि क्यों एथेनॉल सम्मिश्रण को नीति निर्धारण में इतना अधिक महत्व दिया गया है। विदेशों से खरीदा जाने वाला कच्चे तेल का प्रत्येक बैरल देश को कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा आपूर्ति संबंधी उन जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। भारत में उत्पादित गन्ने, मक्का तथा चावल से निर्मित एथेनॉल देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए इस निर्भरता को कम करने का एक प्रभावी माध्यम प्रदान करता है। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2014-15 से (मई 2026 तक) इस कार्यक्रम ने ऐसे परिणाम दिए हैं, जो कागजों पर दर्ज नीति लक्ष्यों से कहीं अधिक व्यापक हैं।

यहाँ एथेनॉल सम्मिश्रण से जुड़ी प्रमुख चिंताओं तथा सोशल मीडिया पर प्रचलित विभिन्न भ्रामक धारणाओं पर साक्ष्य-आधारित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं।

दावा : तथ्य :-

ई20 से माइलेज में 30 प्रतिशत की कमी आती है। :-

30 प्रतिशत का आंकड़ा केवल पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल के कम ऊष्मीय मान (कैलोरिफिक वैल्यू) से संबंधित है, न कि वास्तविक परिस्थितियों में माइलेज में होने वाली कमी से। वास्तविक माइलेज ईंधन के प्रकार की अपेक्षा वाहन चलाने की शैली, टायरों में वायु-दाब, वाहन के रख-रखाव तथा एयर कंडीशनर के उपयोग जैसे कारकों पर कहीं अधिक निर्भर करता है। ई20 से इंजन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, विशेषकर पुराने वाहनों के इंजन। :-

ई20 के लागू होने के बाद इससे संबंधित इंजन विफलता का कोई व्यापक पैटर्न सामने नहीं आया है। वाहन निर्माताओं के सहयोग से सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा व्यापक परीक्षणों के उपरांत ही ई20 को स्वीकृति प्रदान की गई।

एथेनॉल उच्च प्रदर्शन देने वाला ईंधन नहीं है और इससे वाहन के प्रदर्शन में कमी आती है। :-

एथेनॉल एक उच्च ऑक्टेन ईंधन है, जिसकी अनुसंधान ऑक्टेन संख्या (आरओएन) लगभग 108.5 है, जबकि पेट्रोल की यह संख्या लगभग 84.4 होती है। ई20 भारतीय पेट्रोल की प्रभावी ऑक्टेन संख्या को बढ़ाकर लगभग 95 तक पहुंचा देता है, जिससे आधुनिक इंजनों में दहन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। ई20 के अनुरूप कैलिब्रेट किए गए वाहन बेहतर त्वरण (एक्सेलेरेशन), अधिक सुगम प्रदर्शन तथा कम उत्सर्जन प्रदान कर सकते हैं।

ई20 से संबंधित क्षति के मामलों में बीमा कंपनियाँ दावा स्वीकार नहीं करतीं। :-

बीमा कंपनियों तथा मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) ने स्पष्ट किया है: भारत में ई20 के उपयोग का बीमा या वारंटी की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि विनिर्देशों के अनुरूप ई20 का उपयोग करने वाले वाहनों की वारंटी का सम्मान किया जाएगा।

एथेनॉल मिश्रित ईंधन सस्ता होना चाहिए, लेकिन सरकार मूल्य का अंतर अपने पास रख रही है। :-

इस दावे के समर्थन में उद्धृत नीति आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2020-21 की है, जब एथेनॉल वास्तव में पेट्रोल की तुलना में सस्ता था। इसके बाद एथेनॉल की खरीद लागत परिष्कृत पेट्रोल की लागत से अधिक हो गई है, फिर भी ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय लाभ तथा किसानों की आय में वृद्धि जैसे दीर्घकालिक लाभों को देखते हुए एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम जारी रखा गया है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि ई20 केवल एक श्प्रयोगश है। :-

यह मामला एथेनॉल खरीद अनुबंधों से संबंधित था, न कि ई20 की उपयोगिता या उपयुक्तता से। 30.06.2026 को महान्यायवादी के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि ई20 को केवल श्प्रयोगश बताए जाने का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है।

गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिला दिया जाता है। :-

पेट्रोल में कच्चा रस मिलाते हुए दिखाए जाने वाले वायरल वीडियो भ्रामक हैं। एथेनॉल का उत्पादन किण्वन तथा औद्योगिक प्रसंस्करण की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिससे उसके गुण पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं। पेट्रोल में सम्मिश्रण से पहले उसे ईंधन गुणवत्ता से संबंधित कड़े विनिर्देशों को पूरा करना अनिवार्य होता है।

एक लीटर एथेनॉल के उत्पादन में 10,000 लीटर पानी की खपत होती है। :-

एक लीटर एथेनॉल के उत्पादन में एथेनॉल संयंत्र में केवल 3 से 5 लीटर प्रसंस्कृत जल का उपयोग होता है। आधुनिक आसवनी (डिस्टिलरी) संयंत्र शून्य द्रव अपशिष्ट (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) प्रणाली पर संचालित होते हैं। धान की खेती में प्रयुक्त संपूर्ण वाटर फुटप्रिंट को एथेनॉल उत्पादन से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत है। एथेनॉल उत्पादन के लिए केवल वही अधिशेष चावल उपयोग में लाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित किया जाता है।

ई20 में चीनी होने के कारण चींटियाँ और मधुमक्खियाँ ईंधन टैंक के ढक्कन के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं।

ईंधन-ग्रेड एथेनॉल आसवन प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, जिसमें अवशिष्ट शर्करा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसमें कीट-प्रतिरोधी विकृतीकारक (डिनैचुरेंट) मिलाए जाते हैं, पेट्रोल की गंध प्रमुख रहती है तथा ई20 से सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम वाष्प बनती है।

एथेनॉल की जल अवशोषित करने की प्रकृति ईंधन को खराब कर देती है और ईंधन टैंक को नुकसान पहुँचाती हैईंधन टैंक में पानी का प्रवेश रोकना प्रत्येक वाहन की मूलभूत अभिकल्पना का हिस्सा होता है, चाहे उसमें एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग किया जाए या नहीं।

स्वामी एवं प्रकाशक मौ. वसी के लिये मुद्रक नुसरत निशान खान द्वारा कौमी गुलदस्ता प्रिंटर्स, विलेज आमवाला, पोस्ट घंघौरा, देहरादून द्वारा, उत्तराखण्ड-248141 से मुद्रित एवं 5, लेन नम्बर 2, नामदेव एन्क्लेव फेस 2, ब्राहम्णवाला, देहरादून उत्तराखण्ड- 248171 से प्रकाशित। सम्पादक-मौ. वसी,
समस्त विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून मान्य होगा। सम्पर्क- 9411112331

हमारे अखबार के ताजा अंक को ऑनलाइन पढ़ने के लिये www.aawamindia.com वेबसाइट पर जायें।
facebook: www.facebook.com/indiaaawam, youtube:www.youtube.com/@aawamindia,
X:www.x.com/aawamindia, Instagram:https://instagram.com/aawamindia